राज्य में पसरते जा रहे हैं डेंजर जोन

तीन साल में एक गांव भी पूरा विस्थापित नहीं, 449 पहुंची संवेदनशील गांवों की संख्या

बृजमोहन खर्कवाल

पौड़ी। राज्य में भूस्खलन का खतरा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हर साल कई गांव डेंजर जोन में आ रहे हैं। आज ऐसे संवेदनशील गांवों की संख्या में दो सौ से अधिक गांवों का इजाफा हो गया है। सरकारी प्रयासों की बात करें तो वर्ष 2010 में संवेदनशील घोषित 233 गांवों में से अभी एक गांव को भी पूरी तरह सरकार विस्थापित नहीं कर पाई है। वर्ष 2011 में विस्थापन नीति भी बनाई गई, पर अभी तक इनमें सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले के छातीखाल गांव का आधा अधूरा विस्थापन हो पाया है। अन्य 232 गांवों का सर्वे भी नहीं हो पाया है। जबकि आज डेंजर जोन के गांवों की संख्या बढ़कर 448 पहुंच चुकी है।

जिलों से संकलित रिपोर्ट के अनुसार

पौड़ी जिले में डेंजर जोन में शामिल गांव

तहसील	गांव
लैंसडाउन	पल्लीगांव, मोहरा वल्ला, ढौरी, सिमलसैण, तोल्यूं डांडा, मेलधार, सिद्धपुर
धूमाकोट	डुंगरी मल्ली, कसाणा, तलकाण्डई
कोटद्वार	चूना महेड़ा, मवासा, धूरा भरपूर, स्यालकंडी, सिमिल्या, सिमलना बिचला, केष्टा, बढरौ
यमकेश्वर	कसाणगांव, रामणीरेकर, आमकाटल, गढ़कोट, भू-खण्डी, क्वीराल गांव, दिबोगी, जोग्याणा
चौबट्टाखाल	रिंगवाड़ी, कमेड़ी, छामाछोटा, छामा बड़ा, मथाणा
थैलीसैण	डुमलोट, भैखोली, जैंती, खेतोली, सतपुली
तहसील	उच्चाकोट, पातलगांव, पौड़ी, बन्तापानी, चौबट्टा, पाबौ, सिमखेत

वर्ष 2010 में विस्थापन को चयनित गांव

पौड़ी-19, टिहरी-19, चमोली-49, उत्तरकाशी-05, रुद्रप्रयाग-01, देहरादून-02, पिथौरागढ़-71, चंपावत-09, अल्मोड़ा-09, बागेश्वर 42, नैनीताल-06, ऊधम सिंह नगर-01

वर्ष 2013 में संवेदनशील गांवों की संख्या

पौड़ी-42, टिहरी-36, चमोली-74, उत्तरकाशी- 103, रुद्रप्रयाग-21, देहरादून-2, पिथौरागढ़-74, चंपावत-9, अल्मोड़ा-29, बागेश्वर-48, ऊधम सिंह नगर-1, नैनीताल-11

इनका कहना है

''वर्ष 2010 में भूस्खलन के लिए संवेदनशील घोषित गांवों में से एक गांव का विस्थापन हुआ है जिसमें कुछ परिवार अभी विस्थापित होने बाकी है। बाकी अन्य गांव अभी विस्थापित नहीं हो पाए हैं।'' - ***डा. पीयूष रौतेला,*** *अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून*

''भूस्खलन के लिए संवेदनशील घोषित गांवों में कई सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। कुछ का सर्वेक्षण किया जा चुका है। विस्थापन की कार्रवाई हेतु कुछ गांव चयनित भी किए गए हैं। बजट के अभाव से कार्रवाई अभी लंबित है।'' - ***संतोष बड़ोनी,*** *अनुसचिव, आपदा प्रबंधन उत्तराखंड*

''भूस्खलन के लिए संवेदनशील गांवों के विस्थापन को शासन को पत्र भेजा जा चुका है। मामला शासन स्तर पर है। शासन की मंजूरी के बाद ही कार्रवाई होगी।'' - ***चंद्रेश कुमार यादव,*** *जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल*